



भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव



लेखक

डॉ. राजेश मौर्य

सहा. प्रा. अर्थशास्त्र

शास. नेहरू महा. वि. सबलगढ़

जिला-मुरैना

ईमेल – dr.rajeshmorya@gmail.com



डॉ. रूपेन्द्र वर्मा

सहा. प्राध्यापक गणित

शास. नेहरू महा. वि. सबलगढ़

जिला-मुरैना

सार:-

वर्तमान में संचालित वैश्वीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया हैं, जिसके अन्तर्गत विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ दिया जाता हैं। इसके अन्तर्गत एक देश दूसरे देश में वस्तुओं व सेवाओं के क्रय-विक्रय से लेकर निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उद्योग-धंधे आदि स्थापित कर सकता हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया कोई नयी अवधारणा नहीं हैं, बल्कि 5000 वर्ष पुरानी हैं, लेकिन वर्तमान में जो वैश्वीकरण संचालित हैं, वह 1960 के दशक से आरंभ हुयी हैं।

भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत सन 1990-91 के दशक से हुयी हैं, क्योंकि इसी दशक में हमारे प्रधानमंत्री श्री पी. व्ही. नरसिंह राव जी ने देश का आर्थिक सुधार कार्यक्रम संचालित किया था। जिसमें निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों को अमल में लाया गया था। जब से भारत में इसकी शुरुआत हुयी हैं, तब से भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनेक सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हुये हैं। आर्थिक विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद, विदेशी व्यापार, निवेश तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, भारतीयों के जीवन स्तर में वृद्धि तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी इत्यादि में आशातीत वृद्धि हुयी हैं। आँकड़ों से स्पष्ट होता हैं कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.5% (2019-20)



पर पहुँच गया है और यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्ष 2050 तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़कर 302.4 अरब अमेरिकी डालर पर पहुँच गया है, जबकि बौद्धिक सम्पदा अधिकार, जिसे एक देश की मूल्यवान सम्पत्ति कहा जाता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बौद्धिक सम्पदा सूचकांक के अनुसार विश्व के 137 देशों में से भारत 52 वे स्थान पर है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर हुये हैं और भविष्य में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत एक दिन विश्व की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था होगी।

फोकस क्षेत्र:—

वैश्वीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, सकल घरेलू उत्पाद, बौद्धिक सम्पदा अधिकार।



प्रस्तावना:—

सामान्य शब्दों में अर्थव्यवस्था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत आय, उपभोग, उत्पादन, निवेश व रोजगार आदि लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये एक प्रक्रिया के रूप में सुचारु रूप से चलायमान रहती है, जबकि वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ देने से है अर्थात् वैश्वीकरण की अवस्था में एक देश, दूसरे देश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिये खोल देता है। अब वह दोनों देश एक-दूसरे देश में जाकर उत्पादन से लेकर वस्तुओं व सेवाओं को स्वतंत्रापूर्वक विनिर्माण तथा क्रय-विक्रय की प्रक्रिया कर सकता है।

विश्व के विभिन्न अर्थशास्त्रियों तथा सामाजिक-आर्थिक दार्शनिकों का कहना है कि वैश्वीकरण कोई नयी अवधारणा नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है। एम तेहरैन (M. Tehranian) का कहना है कि वर्तमान में जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया संचालित है, वह लगभग 5000 से भी अधिक पुरानी है,¹ तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि आज दुनियाँ के सभी देश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमने अधिकांश विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यहाँ पर भी यह कथन लागू होता है। जब तक मनुष्य को इसकी जरूरत नहीं हुयी, तब तक यह अवधारणा (वैश्वीकरण) गुमनामी के अंधेरे में थी, लेकिन आज के बदलते परिवेश, लोगों की बढ़ती हुयी आवश्यकतायें, तकनीकी विकास तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के महत्व के कारण आज इसे अमल में लाना आरंभ कर दिया है। वास्तविक रूप में वैश्वीकरण शब्द की शुरुआत 60 के दशक में सोवियत संघ (यू.एस.एस.आर.) के विघटन के परिणामस्वरूप दिखायी दी थी।²

भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ उस समय से माना जाता है, जब से भारतीय प्रधानमंत्री श्री पी.व्ही. नरसिंहराव के नेतृत्व में आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया था और यह वर्ष था सन 1990-91, ऐसा अनुमान है कि सन 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं देखा गया था, लेकिन जैसे ही आर्थिक सुधार कार्यक्रम संचालित हुआ, वैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्णकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ था। **ऑकड़ो से**



स्पष्ट होता है कि सन 1991 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 270 बिलियन डॉलर था, जो कि आज अर्थात् वर्ष 2019 में बढ़कर 2.87 ट्रिलियन डॉलर हो गया है और यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्ष 2026 तक यह 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जायेगा।³

यह शोध पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या मूलचूल परिवर्तन हुये तथा किस प्रकार से वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर पहुँचाया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

वैश्वीकरण नामक शब्द का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ही विचार उत्पन्न होता है और वह है विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण अर्थात् अब कोई भी देश किसी भी अन्य देशों में वस्तुओं व सेवाओं से लेकर अपनी भावनाओं, विचारों को पहुँचा सकता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने न केवल मानव के जीवन स्तर को परिवर्तित किया है बल्कि विभिन्न देशों की आर्थिक विकास की प्रक्रिया को भी परिवर्तित करके शीर्ष स्तर पर पहुँचा दिया है, परन्तु इस अवधारणा का उद्भव कैसे हुआ? कौन-कौन सी परिस्थितियों से गुजरते हुये इस मुकाम पर पहुँचा आदि के संबंध में जब हम इसके ऐतिहासिक पक्ष पर दृष्टि डालते हैं, तो हमें कुछ आश्चर्य जनक तथ्य या तर्क प्राप्त होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वैश्वीकरण की अवधारणा का जन्म प्राचीन काल की व्यापारिक राजनैतिक प्रणालियों से हुआ है, जबकि कुछ लोग वैश्विक संस्कृति को मानते हैं। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि अब अवधारणा आर्थिक संकटों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुयी विश्व की राजनैतिक स्थिति जिम्मेदार है। इतिहासकार तथा अर्थशास्त्री, जिनमें विश्व के अधिकांश विद्वान शामिल हैं, समुद्री मार्गों के माध्यम से विभिन्न लोगों द्वारा की गयी यात्राओं को वैश्वीकरण का उद्भव मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब लोग एक देश से दूसरे देशों में यात्राएँ करते थे तो एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ, जिसने आगे जाकर उसे वैश्विक संस्कृति में परिवर्तित कर दिया था। इन सब आश्चर्य जनक तथ्यों के आधार पर अब हम क्रमबद्ध रूप से वैश्वीकरण के ऐतिहासिक पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे।

विश्व में 1400 ई.पू. का दशक एक अन्वेषण युग के नाम से जाना जाता था। जिसके तहत दुनिया में नये-नये आविष्कार हुये थे। कुछ लोगों का कहना है कि इस युग



में वैश्वीकरण की शुरुआत हो चुकी थी।⁴ उन्होंने तर्क दिया कि जब यूरोपीय लोगों को ज्ञात हुआ कि एशिया महाद्वीप के कुछ देशों में मसाला नाम की एक चीज या वस्तु पायी जाती हैं। जिसे प्राप्त करने के लिये यूरोपीय लोगों ने अटलांटिक के पार भारत तथा चीन जैसे देशों की समुद्री मार्गों के माध्यम से तलाश की थी। इस समुद्री मार्ग को अंजाम देने में क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम अहम था। कहा जाता है कि इसी खोज की वजह से वैश्वीकरण की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि कुछ विद्वान इसके उदय को पश्चिम के उदय से जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि विश्व में जैसे-जैसे शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पैर जमाने शुरू किये वैसे-वैसे वैश्वीकरण का आरंभ हुआ।⁵

हमारी दुनिया में कुछ ऐसे आर्थिक विश्लेषक हुये हैं। जिन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उस समय वैश्वीकरण जैसा शब्द आर्थिक कारकों तथा विश्व एकीकरण पर केन्द्रित था। जिसके तहत वस्तुओं व सेवाओं का एक देश से दूसरे देश तक आदान-प्रदान होता था अर्थात् सम्पूर्ण दुनिया में वस्तुओं एवं मुद्राओं का मुक्त प्रवाह होता था जबकि कुछ विश्लेषण कहते हैं कि इस ऐतिहासिक विकास को आकार देने में उस समय की राजनैतिक प्रणालियों ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी, क्योंकि उस समय अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्थानों, कानूनों व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न विकास संस्थानों एवं निकायों का गठन हो चुका था, जो कि व्यापार के संबंध में विभिन्न राष्ट्रों के बीच उत्पन्न विवादों को हल करने का काम करते थे।

विश्व के कुछ इतिहासकार तथा अर्थशास्त्रियों ने यह माना कि 1500 ई.पू. में दुनिया के विभिन्न देशों में वैश्वीकरण की शुरुआत हो चुकी थी, परन्तु इस अवधि को लेकर विभिन्न विद्वान एकमत नहीं हैं। आन्द्रे गुंडर फ्रैंक (1998) का कहना है कि 1500 ई.पू. के बाद सम्पूर्ण दुनिया में बहु-पक्षीय व्यापार तथा श्रम विभाजन के बाद विश्व अर्थव्यवस्था एक वैश्विक अर्थव्यवस्था थी।⁶ जबकि जैरी बेंटले का तर्क है कि 1500 ई.पू. के पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था दृष्टिगोचर हो चुकी थी। इसे स्पष्ट करने के लिये उन्होंने तर्क दिया है कि उस समय यूरेशिया से लेकर उप सहारा अफ्रीका तक व्यापार फैल चुका था तथा कृषि, वाणिज्य एवं औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया था।⁷ वे (बेंटले) 1500 ई. पू. की बाद की अवधि को एक विश्व इतिहास की वास्तविक वैश्विक युग के उदभव के रूप में देखते हैं।⁸



विश्व के कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि सन 1800 का दशक, जिसे विश्व इतिहास में स्वर्ण मानक (सोने के सिक्के) के युग के नाम से जाना जाता है, वैश्वीकरण की लहर उत्पन्न हो चुकी थी। इस अवधि में व्यापक पैमाने पर कई व्यापारिक कंपनियों एवं दास उद्योग संचालित थे।⁹ ऐसा अनुमान है कि इस दशक में विश्व में सोने का उपयोग अपने देश की मुद्रा के मानक के रूप में किया जाता था। जब यूरोपीय देश इंग्लैण्ड ने अपनी मुद्रा के मूल्य को सोने (स्वर्ण) में निर्दिष्ट करना आरंभ किया तो अन्य देशों ने भी इंग्लैण्ड के समान सोने का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप एक विशेष अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण का शुभारंभ हुआ था, हालाँकि कई इतिहासकारों ने यह भी कहा था कि 1800 के दशक में जो विश्व अर्थव्यवस्था थी, अपनी खराब या जर्जर अवस्था में थी, क्योंकि उस समय यह लंबी दूरी की यात्रा से व्यापार होता था, इसलिये समय अधिक लगने के कारण यह अर्थव्यवस्था उचित नहीं थी।

इमैनुएल वालरस्टीन (1989) का कहना है कि – “1750 से 1850 की अवधि में दुनिया के अनेक हिस्सों जैसे – भारत, ओटोमन साम्राज्य, रूस, पश्चिमी अफ्रीका आदि देश विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल हो गये थे, क्योंकि इस अवधि में विलासित की वस्तुओं को थोक वस्तुओं के व्यापार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।”¹⁰

जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो विश्व की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था तहस-नहस (जर्जर) हो गयी थी, तब अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार हेतु विश्व के राष्ट्रों के बीच उत्पन्न बाधाओं को तोड़ने के लिये तथा मुक्त या स्वतंत्र व्यापार हेतु अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गयी थी, जिनमें सन 1944 में ब्रेडन बुडस सम्मेलन के दौरान स्थापित किये गये, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक आदि थे।¹¹ इन संगठनों को वैश्वीकरण के रूप में जाना गया था, क्योंकि इनका मुख्य कार्य विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का उद्धार करना था और इसके बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं को दुनिया का महाशक्ति के रूप में स्थापित किया था।

सन 1990 के दशक में प्रसिद्ध टोम फ्रीडमैन की प्रसिद्ध व प्रभावशाली पुस्तक – “द लेक्सस एण्ड द ओलिव ट्री” नामक पुस्तक आयी। जिसमें शीत युद्ध की समाप्ति तथा इन्टरनेट के विस्फोटक उपयोग का वर्णन मिलता है, जो यह स्पष्ट करता है कि वैश्वीकरण



का आरंभ हो चुका था। इसके बाद फ्रीडमेन ने तारीख को आगे बढ़ाकर 21वीं सदी की शुरुआत से जोड़ दिया था।

हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों के बीच भिन्नता होने के कारण वैश्वीकरण के शुरुआत की कोई एक निश्चित तिथि नहीं है, परन्तु यह जरूर कहा जा सकता है कि वास्तव में आज वैश्वीकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों से लेकर विलासिता की वस्तुओं तक एक प्रकार की क्रॉति प्रज्वलित की थी, जिसकी वजह से आज हम वस्तुओं व सेवाओं के संबंध में हमारे पास अनेक विकल्प उपलब्ध हैं।

वैश्वीकरण की अवधारणा:—

आज सम्पूर्ण विश्व जैसे-जैसे प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है, वैसे-वैसे लोगों की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती जा रही है। अब व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध तथा गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं एवं सेवाओं की आवश्यकता है। इस दृष्टि से पुराने बाजार उपभोक्ताओं की मांगों को संतृप्त करने में विफल रहे हैं, पुराने बाजारों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उपभोक्ताओं की इच्छायें क्या हैं? तथा उन्हें कैसे पूर्ण किया जायें, इन्हीं सब कारणों की वजह से एक ऐसे बाजार की मांग उत्पन्न हो गयी है, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो, जिसे हम आज वैश्वीकरण कहते हैं।

आज हमारे व्यवहार, समाज व अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का प्रचलन इतना अधिक हो गया है कि यह प्रत्येक क्षेत्र में अपने पैर जमाये हुये हैं। बेबस्टर डिक्शनरी ने सन 1944 में यह स्पष्ट किया कि वैश्वीकरण आज के समय का एक फेशनेबल शब्द हो गया है। अब इसका उपयोग राजनेताओं, कलाकारों, व्यापारियों, पर्यावरण संरक्षण के विशेषज्ञों तथा समाजशास्त्रियों व अर्थशास्त्रियों के बीच प्रचलन में आ गया है।¹² यही नहीं बल्कि विभिन्न आर्थिक आयामों जैसे – व्यापार, धन, बैंकों, बीमा कंपनियों व पूँजी बाजार इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। कई सामाजिक-आर्थिक दार्शनिकों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भविष्य में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण के अभाव में नहीं चल सकती है।

वैश्वीकरण की निम्नलिखित परिभाषायें हैं –



एम फ्रायडमैन (M Friedman) के अनुसार – “हालाँकि वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न राष्ट्रों एवं सदस्य राष्ट्रों का एकीकरण हैं, लेकिन फिर भी आज इसका उपयोग प्रौद्योगिकियों, व्यक्तियों, निगमों में बहुत तेजी से किया जा रहा है। जिसने न केवल उत्पादों को सस्ता व आसान बनाया है बल्कि सभी लोगों की पहुँच को भी सरल बनाया है।”¹³

ए. एफ. फिरात (A.F. Firat) के अनुसार – “सम्पूर्ण विश्व में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक रूप से गरीब देशों से लेकर समृद्ध राष्ट्रों तक में एक समान रूप से लोगों की जीवन शैली, उपभोग, पद्धति, उत्पाद व सांस्कृतिक अनुभवों को बढ़ावा दिया है।”¹⁴

एम. टी. जॉन्स (M. T. Jones) के अनुसार – “वैश्वीकरण विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं के पार उत्पाद, वित्तीय प्रवाह और श्रम बाजारों के निरंतर एकीकरण के रूप में जाना जाता है।”¹⁵

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण दुनिया के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने की प्रक्रिया है अर्थात् अब कोई भी देश किसी भी देश में जाकर अपने उत्पादों का क्रय-विक्रय, नवीनतम तकनीकी का हस्तांतरण, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का विस्तार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि स्थापित कर सकता है।

वैश्वीकरण ने न केवल उत्पादों व वित्तीय प्रवाह को आदान-प्रदान करने में सहयोग किया है बल्कि लोगों की जीवन शैली, उनका रहन-सहन का स्तर व संस्कृति एवं सभ्यता को भी परिवर्तित कर दिया है, इसीलिये वैश्वीकरण को एक बढ़ता हुआ पूँजीवाद का नाम दिया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:-

हम पूर्व में जान चुके हैं कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत सन 1990-91 से मानी जाती है। हमारे देश में इसकी शुरुआत का मुख्य कारण देश की भीवत्स आर्थिक समस्याएँ थी, जैसे:- आय का निम्न स्तर, घटता हुआ निवेश व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भुखमरी, बेरोजगारी, बेकारी आदि थी, जिन्हें समाप्त करने के लिये भारत सरकार ने अपनी नीतियों को परिवर्तित किया और एक ऐसी अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जिसमें कोई भी विदेशी निवेशक भारत में आकर अपना व्यवसाय या उद्योग स्थापित कर सके अर्थात् कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया गया था,



जिसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर हुये हैं।

i. सकल घरेलू उत्पाद:—

विश्व में जितने भी विकासशील देश हैं, उनमें से भारत ही ऐसा रहा है, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिये अपनी नीतियों को सबसे अधिक उदारवादी तथा लचीला बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप देश के सकल घरेलू उत्पाद में आश्चर्यजनक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुये हैं।

भारत ने वर्ष 1990-91 में वैश्वीकरण में जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही अपनी आर्थिक नीतियों (लायसेंसिंग, उदारवादी) जैसे:— भारत में बहु राष्ट्रीय कंपनियों के आगमन पर लगी रोक को हटाना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति देना, देशी निवेशकों को विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान टैरिफ तथा अन्य करों की दरों में उदारवादी को प्रोत्साहित करना और विदेशी सहयोग आदि नतीजतन देश की विकास दर अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद में आशातीत वृद्धि की स्थिति दर्ज की गयी थी। वर्ष 1990-91 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम के कारण देश का सकल घरेलू उत्पाद 0.9% था, जो कि वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 2003-04 में बढ़कर क्रमशः 5.3%, 6.2% एवं 8% तक की वृद्धि दर्ज की गयी थी।¹⁶ यदि हम 1990 के पूर्व की स्थिति पर दृष्टि डालें तो यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1970 में देश की विकास दर 3% थी, जो कि कोरिया, मैक्सिको, ब्राजील तथा इण्डोनेशिया जैसे देशों की विकास दर से बहुत कम थी। यही स्थिति 1980 के दशक में दर्ज की गयी थी अर्थात् स्पष्ट है कि भारत के वैश्वीकरण में प्रवेश होने से देश की विकास दर में सुधार हुआ है। आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 1991 में भारत का स्थान 8वाँ था, जो कि वर्ष 2009 में घटकर 4 स्थान पर आ गया है।¹⁷

किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद बाजार पूँजीकरण पर निर्भर करता है और बताता है कि वहाँ के निवेशकों की स्थिति कैसी है। इस दृष्टिकोण से भारत काफी अच्छी स्थिति में है। भारत का कुल बाजार पूँजीकरण 3 ट्रिलियन डॉलर का है।¹⁸ यदि हम भारत की तुलना अन्य देशों से करें तो इसकी स्थिति इस प्रकार होगी।

विभिन्न देशों का कुल बाजार पूँजीकरण (2021)

क्रम	देश	कुल बाजार पूँजीकरण
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	49 ट्रिलियन डॉलर
2	चीन	12.4 ट्रिलियन डॉलर
3	जापान	6.4 ट्रिलियन डॉलर
4	भारत	3 ट्रिलियन डॉलर
Source:- (www.monycontrol.com), 30 May, 2021.		

उपरोक्त तालिका में पूँजीकरण के मामले में सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। उसके बाद चीन, जापान तथा भारत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा देश वैश्वीकरण की वजह से कितना अधिक आगे निकल चुका है, इसीलिये देश की गिनती विश्व के विकसित राष्ट्रों के साथ की जा रही है, हालाँकि वैश्विक बाजार में भारत की भागीदारी की गणना एक सीमांत भागीदार के रूप में की जाती है, लेकिन फिर भी भारत ने इस तरह से अपनी भूमिका पेश की है कि अब वह विश्व के विकसित देशों के साथ अपनी तुलना करने में सक्षम है।

विश्व बैंक ने अभी हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार – “वर्ष 2017 के आँकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ-साथ विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। देश की विकास दर वर्ष 2018-19 में 7.3% तथा 2019-20 में 7.5% हो गयी है।”¹⁹ इस दृष्टि से यह दुनिया की उभरती हुयी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, दूसरी ओर एशिया महाद्वीप का सबसे कम समय में अपनी विकास दर में वृद्धि करने वाला देश चीन, जिसकी विकास दर उच्च होती थी, धीरे-धीरे कम हो रही है। वर्ष 2018 में चीन की विकास दर 6.5% थी, जो कि वर्ष 2019 में कम होकर 6.3% पर पहुँच गयी है।²⁰ चीन के ये आँकड़ें बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्य में काफी आगे निकल सकती है, तो क्या वास्तव में यह सत्य हो सकता है। इसके संबंध में यूनाइटेड स्टेट का विभाग “कृषि के लिये आर्थिक अनुसंधान संघ” का यह दावा है कि – “भारत, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान ये चार देश वर्ष 2030



तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।²¹ इसी प्रकार पीडब्लूसी ने एक रिपोर्ट "2050 में विश्व" नामक जारी की हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि विश्व के जितने भी उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, दो गुना तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।²² इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य संबंधी अनुमानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि – "वर्ष 2050 तक विश्व की सात सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से दो, जिसमें चीन, भारत शामिल हैं, क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर होगी तथा विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, वैश्विक जी.डी.पी. रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हो सकता है।"²³

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने से पूर्व की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में आ गया है अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद या विकास दर के मामलों में तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। इसका कारण तेजी से औद्योगिक विकास व सेवा क्षेत्र में बढ़ता हुआ योगदान है। हमने जैसे ही 1990-91 में वैश्वीकरण को अपनाया, वैसे ही बहु-राष्ट्रीय निगमों से लेकर निवेश व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व घरेलू निवेशको को सुविधायें प्रदान की, उनके लिये नीतियों में परिवर्तन किया। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने विकास दर के मामलों में विकसित देशों के समकक्ष आ गयी है और यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि भविष्य में भारत की विकास दर विकसित देशों से भी काफी अधिक होगी।

ii. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार :-

एक देश की सीमाओं से दूसरे देश तक वस्तुओं व सेवाओं के होने वाले आदान-प्रदान को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दो अंगों जैसे – आयात-निर्यात के माध्यम से किया जाता है। एक देश के संदर्भ में दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं व सेवाओं को आयात तथा एक देश से दूसरे देश में जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को निर्यात कहते हैं।

भारत ने 1990-91 में विदेशी व्यापार को महत्व देने के लिये उदारीकरण की नीति को अपनाया था। जिसके तहत टैरिफ (विदेशी व्यापार के दौरान आने वाली वस्तुओं पर लगने वाला कर) बाधाओं को समाप्त करने के साथ-साथ टैरिफ दरों को भी कम किया गया था। जिसने भारत के विदेशी व्यापार में अहम भूमिका निभायी थी।²⁴ वैश्वीकरण की



भूमिका ने न केवल देश के व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि देश के उपभोक्ताओं को व्यापक स्तर पर एक विशाल बाजार भी प्रदान किया। अब वस्तुओं व सेवाओं की अधिकता के कारण उपभोक्ताओं के पास बड़ी मात्रा में विकल्प हैं, जिनके सहयोग से वे (उपभोक्ता) अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हुये हैं। व्यापक स्तर पर कंपनियों और उद्योगों (बहु-राष्ट्रीय निगम) के आगमन से वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति निर्मित हुयी है – जिसने न केवल विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण नवाचारों को बढ़ावा दिया है बल्कि नयी-नयी उत्पादन पद्धतियाँ, गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद और नये उत्पादों की खोज के साथ बाजार में जो एकाधिकार की स्थिति थी, उसे समाप्त किया है।²⁵ इससे अनेक विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ है, क्योंकि हमारा देश अधिक जनसंख्या होने के कारण सर्वाधिक माँग को प्रेरित करता है और इसी माँग ने हमारे निर्यात व आयात की मात्रा को बढ़ाया है। नतीजतन विश्व में वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी, जो कि 1990-91 में मात्र 0.5% थी, बढ़कर 2018 में 2.1% हो गयी है।

भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार – “वर्ष 2017-18 में भारत ने विदेशी व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है अर्थात वैश्विक व्यापार की दृष्टि से भारत का कुल व्यापार 767.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है।”²⁶ जिसने हमारे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज की है। विश्व बैंक के अनुसार – “भारत ने वर्ष 1990 से 2017 तक वस्तुओं व सेवाओं के आयात-निर्यात के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद में कुल 55% की वृद्धि दर्ज की है।”²⁷ वैश्वीकरण ने पिछले दो दशकों में भारत के कुल व्यापार में छह गुना से भी अधिक की वृद्धि की है। आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2000 से 2001 तक कुल 44.5% अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की है, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 302.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है,²⁸ हालाँकि भारत ने अपने व्यापार में ऐसी स्थिति का भी सामना किया है, जिसमें विदेशी व्यापार स्थिर रहा है अर्थात आयात-निर्यात की स्थिति में उतार-चढ़ाव देखा है और यह वर्ष था 2009-10, ऐसा अनुमान है कि यह स्थिति उसी प्रकार की थी, जिस वर्ष अर्थात 2008 में भारत वित्तीय संकट से जूझ रहा था। इसके कई कारण थे, जैसे – वैश्विक माँग में गिरावट, यूरो क्षेत्र में बढ़ता हुआ संकट (यूरो आज एक वैश्विक मुद्रा है) तथा वस्तुओं एवं सेवाओं

की गिरती हुयी कीमतें आदि जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारा आयात पिछले दो दशकों में बढ़कर नौ गुना हो गया था। **ऑकड़ों के अनुसार** – “भारत में वर्ष 2000-01 में कुल आयात 50.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि वर्ष 2017-18 में बढ़कर 459.67 बिलियन डॉलर हो गया था,”²⁹ लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि आयात की तुलना में निर्यात में भी थोड़ी मात्रा में वृद्धि दर्ज की है।

वर्ष 1995-96 से 2017-18 तक की अवधि में भारत की कुल निर्यात स्थिति

	मर्दे (वस्तुएँ व सेवार्ये)	1995-96	2005-06	2017-18
1	प्राथमिक उत्पाद	23 बिलियन डॉलर	15 बिलियन डॉलर	13 बिलियन डॉलर
2	विनिर्माण उत्पाद	75 बिलियन डॉलर	70 बिलियन डॉलर	69 बिलियन डॉलर
3	पेट्रोलियम उत्पाद	1 बिलियन डॉलर	11 बिलियन डॉलर	12 बिलियन डॉलर
4	अन्य उत्पाद	1 बिलियन डॉलर	2 बिलियन डॉलर	6 बिलियन डॉलर

Source:- RBI Handbook of Statistics on Indian Economy- 2017-18.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत निर्यात की दृष्टि से प्राथमिक उत्पादों में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखी गयी थी, जबकि विनिर्माण के क्षेत्र में थोड़ा अन्तर दिखायी दिया है, परन्तु पेट्रोलियम के क्षेत्र में काफी शीर्ष स्थिति में पहुँच गया है। इस प्रकार भारत ने वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में उन्नति की स्थिति अर्जित की है।

iii. बौद्धिक सम्पदा अधिकार:-

किसी भी देश के सन्दर्भ में बौद्धिक सम्पदा अधिकार, वे लोग होते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, जैसे:- इंजीनियर, चिकित्सक, प्रबंधक के क्षेत्र में उपाधि प्राप्त लोग या विद्यार्थी, व्यापारी, निवेशक आदि। ये विशेषज्ञ एक देश के लिये उसकी मूल्यवान सम्पत्ति माने जाते हैं, क्योंकि देश का विकास इन्हीं लोगों पर निर्भर करता है। जब ये लोग एक देश से दूसरे देश में नौकरी या रहने के लिये प्रवासन कर जाते हैं, तो



उन्हें गैर-प्रवासी कहा जाता है। भारत के संदर्भ में ऐसे लोगों को गैर-प्रवासी भारतीय कहा जाता है। इसमें न केवल किसी देश के विशेषज्ञ या व्यक्ति शामिल हैं बल्कि ज्ञान, नवप्रवर्तन, प्रौद्योगिकी, कोई विशेष प्राकृतिक संसाधन इत्यादि भी शामिल होते हैं।

वैश्वीकरण के कारण बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को एक देश से दूसरे देशों में तेजी से स्थानांतरण हुआ है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। हमारे देश में ऐसे (बौद्धिक सम्पदा) प्रवासियों का एक बड़ा भाग मौजूद है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने यह दावा किया है कि – “वर्ष 2006 से 2016 तक की अवधि में नये प्रवासियों की दृष्टि से भारत अपने चौथे स्थान पर बरकरार है। ओ.ई.सी.डी., जो कि विकासशील देशों का एक संघ है, में भारतीयों की एक बड़ी संख्या है, हालाँकि ओ.ई.सी.डी. देशों ने अनेक प्रकार के आब्रजन प्रतिबंधात्मक नियम या कानून पारित किये हैं, परन्तु फिर भी एक बड़ी संख्या में भारतीय लोग मौजूद हैं, चूँकि ये लोग उस देश की मूल्यवान सम्पत्ति होते हैं, क्योंकि इनका उस देश के विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान होता है। इस दृष्टि से अनेक गैर-प्रवासी भारतीय विश्व के शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। बर्सी एस, लिसोनी एफ तथा मिगेलिज ई (Breschi, S., F. Lissoni and E Miguelez, 2019) के द्वारा प्रवासी भारतीयों पर एक अध्ययन किया गया – “जिसमें यह पाया गया कि जितने भी गैर-प्रवासी भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, उनका लगभग 5वां हिस्सा अपने देश (भारत) लौट आता है और उन्होंने अमेरिका में जो भी कौशल हासिल किया है, वह उसे अपने देश में उपयोग करते हैं।”³⁰ इससे देश का विकास संभव होता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ तकनीकी, प्रौद्योगिकी व प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष कौशल अर्जित किया होता है।

व्यक्तियों के नवीन विचार, ज्ञान, नवप्रवर्तन, प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी का जब एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण होता है, तो उस देश का आर्थिक विकास संभव होता है। यह उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों, जैसे – भूमि, खनिज सम्पदा, ऊर्जा, पशु, वनस्पति आदि होते हैं। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के तहत जो भी देश नवप्रवर्तन या तकनीकी के क्षेत्र में जिस चीज या वस्तुओं की खोज करता है, उसे एक कानून के तहत पेटेंट करा लिया जाता है, जिससे कोई अन्य देश इसका गलत उपयोग न कर सके, इस प्रकार पेटेंट किये गये उत्पाद देश के आर्थिक



विकास हेतु उपयोगी होते हैं। जैसा कि औद्योगिक नीति तथा प्रोत्साहन विभाग (2017) ने उल्लेख किया है कि – “किसी भी उत्पाद को पेटेंट करने से न केवल राजनीतिक व्यापारिक नीति है, बल्कि औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा देने वाली एक नीति है।”³¹ इस प्रकार पेटेंट धारण करने वाले देश के संबंध में आर्थिक क्षमता का लाभ उठाने वाला कहा गया है। कायलाविजी और थेनमोझी (Kayalavizhi and Thenmozhi, 2017) ने वर्ष 1996 से 2004 तक की अवधि के आँकड़ों के आधार पर भारत सहित 22 अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया। जिसमें यह पाया कि पेटेंट किये गये उत्पाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं।³² इस दृष्टि से भारत कहाँ पर है? या क्या स्थिति है? के बारे में विश्व आर्थिक मंच (2017) ने स्पष्ट किया है कि – “वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के बौद्धिक सम्पदा संरक्षण में भारत 137 देशों की सूची में 52वें स्थान पर है।”³³

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के कारण बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को सुरक्षा प्राप्त हुयी है और अधिकांश देश इसके आधार पर अपना आर्थिक विकास, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से, भारत ने भी इसी प्रकार अपने अधिकारों को संरक्षित करते हुये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित किया है। जिसका सबसे बड़ा प्रमाण भारत में स्थित असंख्य बहु-राष्ट्रीय निगम हैं और भविष्य में भी भारत अनेक कंपनियों को अपने देश में पूँजी निवेश करने के लिये समय-समय पर प्रोत्साहित कर रहा है।

निष्कर्ष:-

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। आज भारतमें अनेक प्रकार की बहु-राष्ट्रीय कंपनियाँ प्रवेश कर चुकी हैं। जिसने लोगों की माँग को पूरा करने के साथ-साथ सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराये हैं। दूर संचार के क्षेत्र में तो लोगों के बीच एक क्रांति उत्पन्न कर दी है। आज आपको साधारण से साधारण व्यक्ति के पास स्मार्ट फोन देखने को मिल जायेगा और कॉल की दरे तो और भी सस्ती हैं, यही नहीं बल्कि इन्टरनेट कनेक्टिविटी में तो उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुयी है, जिस प्रकार भारत की सबसे



बड़ी व पवित्र नदी गंगा में पानी का प्रवाह होता है और भारत का प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहा है, मेरे ख्याल से वैश्वीकरण की प्रक्रिया का संचालित होना इन सब सुविधाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. M. Tchranian, "Globalism, Localism and Islamism" available online at:- www.hawaii.edu/fred/tchran.
2. Remus Ionut NAGHI (March 2013) The Effects of Globalization on Marketing, Journal of Business Review (GBR). Vol. 2, No 3, March 2013.
3. Top 3 Advantage of globalization in India. (www.safeguardglobal.com) 15 March 2022.
4. Katelyn, P (14 August 2021) When did Globalisation start. (www.investopedia.com), 14 August 2021.
5. Ibid
6. Frank, A.G.(1998) Reorient:- Global Economy in the Asian Age. Berkeley, CA:- University of California Press.
7. Bentley, J. H. (1999). Asia in world history. Education About Asia 4, PP. 5-9
8. Bentley, J.H. (1996). AHR forum – Cross cultural interaction and periodization in world history. American Historical Review 101, PP – 749-770.
9. To see the reference number (4)
10. Wollerstein, I (1989) The modern world-system, Vol. III:- The Second Era of Great Expansion of the Capitalist world-Economy, 1730-1840 San Diego, CA: Academic Press.
11. To see the reference number (4)
12. To see the reference number (2)
13. M Friedman, Capitalism and freedman, Available online at:- www.globalpolicy.org/globaliz/econ/chmsky99.html
14. A.F. Firat, Globalization of Fragmentation:- A Framework for Understanding contemporary Global markets, Journal of International marketing, Vol. 5 No. 2 1997
15. M. T. Jones, "Globalization and Organizational restructuring :- a strategic perspective, Thunderbird International Business Review, Vol. 44, No. 3, 2002, PP. 325-351.
16. UK Essays (November 2018) Role of Indian Economy in Global Market Economic Essay. <https://www.ukessays.com/essays/economics/role-of-indian-economy-in-global-market-economics-essay-php>? vref = 1
17. Ibid
18. Nimish Shah (30 May 2021) Pay More attention to underlying growth of the economy rather than market capitalisation (www.moneycontrol.com) 30 May 2021.
19. World Bank forecasts 7.3% growth for India:- Making it fasted growing economy. "The Economic Times", 6 June 2018.



20. The World bank, Press Release, 5 June 2018, at <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/12018/06/05/global-economy-to-expand-by-3-1-percent-in-2018-slower-growth-seen-ahead>.
21. India's Economy to become 3rd Largest, Surpass Japan, Germany by 2030 "Hindustan Times" (News Paper) April 28, 2017.
22. "The World in 2050", PWC, at <https://www.pwc.com/gx/en/issue/economy/the-world-in-2020.html>.
23. Ibid
24. Panagariya (2004) India Trade reforms:- progress, Impact and Future strategy. <https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/ecoh-wp/it/papers/10403/0403004.pdf>.
25. OECD (2015) the future of productivity, OECD Publishing, Paris, <https://dx.doi.org/10.1787/9789264248533.en>.
26. India's Global Trade rises 16 percent to \$ 767.9 billion in 2017-18, "Economic Times" (News Paper) 25 April 2018.
27. World bank open Data, at <https://data.worldbank.org>.
28. India's Foreign Trade: March 2018, PIB Release, 13 April 2018, at <https://pib.nic.in/newsite/printrelease.aspx?relid=178671>.
29. Ibid
30. Breschi, S., F. Lissoni and E. Miguelez (2019) Does India gain from High Skilled migration to the US? ideas for India, <https://www.ideasforindia.in/topics/productivity-innovation/does-india-gain-from-high-skilled-migration-to-the-us.html>.
31. Department of industrial policy and promotion (2017) scheme for Facilitating start ups. Available at <https://www.ipindia.nic.in/writereaddata/portal/News/323-1-scheme-forfacilitating-start-ups.pdf> (accessed on 29 May 2018.)
32. Kayalvizhi, P.N. and Thenmozhi, M (2017) Does quality of innovation, culture and governance drive FDI Evidence from emerging markets. Emerging market review 34 (2018) pp. 175-191.
33. World Economic Forum (2017), Global competitiveness Report 2017-18. Available at: <https://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-18/competitiveness-ranking#series=EOSQ052> (Accessed on 20 June 2018)